सार्वजनिक सूचना

प्रपत्र संख्या NCLT-13

[राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 के नियम 87 को देखें]

धारा 245 के अंतर्गत याचिका की सार्वजनिक सूचना

सूचना लें कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 245 के अंतर्गत दिनांक 28.02.2024 की एक वर्ग कार्रवाई याचिका, जो कंपनी याचिका संख्या 58 सन् 2024 है, श्री अंकित जैन, सुश्री रीना विरेन्द्र जैन और सुश्री रुचि जैन हनसोगे(सार्वजनिक अल्पसंख्यक शेयरधारक, जो संयुक्त रूप से जिंदल पॉली फिल्म्स लिमिटेड (JPFL) की शेयरधारिता का4.99% धारण करते हैं) द्वारा राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। उक्त याचिकामें मुख्य आवेदक श्री अंकित जैन हैं। उस याचिका में प्रत्यर्थी JPFL, श्री श्याम कुमार जिंदल, सुश्री सुभद्रा जिंदल, श्री भावेश जिंदल, कंसोलिडेटेड फिनवेस्ट्एंड होल्डिंग्स लिमिटेड, कॉन्कैटेनेट एडवेस्ट एडवाइजरी प्राइवेट लिमिटेड, सुश्री सोनल अग्रवाल, श्री संजीव अग्रवाल, श्रीराठी बिनोद पाल, श्री संजीव सक्सेना, श्री देविंदर कुमार रिठालिया, श्री विजेंदर कुमार सिंघल, श्री पुनीत गुप्ता, जिंदलइंडिया पावरटेक लिमिटेड, जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड, जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंस कंपनी लिमिटेड, श्री विनोद कुमार गुप्ता, कंपनी रजिस्ट्रार हैं।

उक्त याचिका धारा 245 में निर्धारित स्वीकृति संबंधी शर्तों को पूरा करती है, जिसमें यह शर्त भी शामिल है कि आवेदनअपेक्षित संख्या में सदस्यों द्वारा किया गया है। धारा 245 की उप-धारा 4 और राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण नियम, 2016 के अंतर्गत उल्लिखित विषय पर विचार करने के पश्चात् न्यायाधिकरण द्वारा 05.02.2026 को आवेदन स्वीकारकिया गया है। आवेदन 02.04.2026 को प्रातः 10:30 बजे या उसके पश्चात् पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए निर्धारितकिया गया है।

याचिका निम्नलिखित आधारों पर दायर की गई है:

i. प्रत्यर्थियों ने JPFL के कोष का ऐसे तरीके से उपयोग किया है जो JPFL के सर्वोत्तम हित में नहीं है और JPFL केसार्वजनिक शेयरधारकों को हानि पहुंचाने के गुप्त उद्देश्य से प्रमोटरों को अत्यधिक कम मूल्यांकन पर निवेश कपटपूर्वकबेचे हैं।

ii. वित्तीय वर्ष 2013-14 से वित्तीय वर्ष 2016-17 तक जिंदल पावरटेक में 0% RPS और 0% OCPS की सदस्यतालेकर INR 703.79 करोड़ का निवेश, इस तथ्य के बावजूद कि जिंदल पावरटेक निरंतर नकद हानि से ग्रस्त था और उसेअनर्जक परिसंपत्ति घोषित किया गया था।

iii. वित्तीय वर्ष 2018-19 में जिंदल पावरटेक और जिंदल थर्मल की नकारात्मक शुद्ध संपत्ति का हवाला देते हुए RPS और OCPS के संबंध में किए गए निवेश को प्रारंभ में राइट ऑफ करना, जबकि बाद में वित्तीय वर्ष 2020-21 औरवित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान उनके संबंधित लेनदारों के बकाये के निपटान की दिशा में INR 410 करोड़ कीअतिरिक्त ऋण राशि प्रदान करना। जिंदल पावरटेक के ऋण का यह समाधान (INR 428.32 करोड़ के ऋण के विरुद्धINR 203 करोड़ के लिए) और जिंदल थर्मल का (INR 9431 करोड़ के ऋण के विरुद्ध INR 2541 करोड़ के लिए) उक्त कंपनियों को INR 7305 करोड़ (ऋणदाताओं की कटौती) के लाभ में परिणामित हुआ।

iv. वित्तीय वर्ष 2019-20 में OCPS की शर्तों में संशोधन और वित्तीय वर्ष 2021-22 में जिंदल थर्मल में जिंदलपावरटेक द्वारा धारित कुछ रिडीमेबल वरीयता शेयरों की शर्तों में संशोधन।

v. जबकि JPFL द्वारा वित्तीय सहायता और OCPS तथा RPS की शर्तों में परिवर्तन और अंततः ऋणदाताओं की कटौतीके परिणामस्वरूप जिंदल पावरटेक और जिंदल थर्मल की शुद्ध संपत्ति में पर्याप्त वृद्धि हुई, JPFL ने अपने निदेशकों केमाध्यम से कार्य करते हुए, वित्तीय वर्ष 2021-22 में उक्त साधनों को मात्र INR 66.03 करोड़ (INR 440.20 करोड़ केवास्तविक मूल्य के विरुद्ध) और INR 39.53 करोड़ (INR 264 करोड़ के वास्तविक मूल्य के विरुद्ध) के अत्यल्पमूल्यांकन पर क्रमशः SSJ ट्रस्ट और जिंदल पॉली इन्वेस्टमेंट को बेच दिया, जिससे लगभग INR 2,500 करोड़ की हानिहुई।

याचिका निम्नलिखित अनुतोष की मांग करती है:

a) SSJ ट्रस्ट (इसके न्यासियों प्रत्यर्थी संख्या 2 और प्रत्यर्थी संख्या 3 के माध्यम से) और प्रत्यर्थी संख्या 16 / जिंदलपॉली इन्वेस्टमेंट को ऐच्छिक रूप से परिवर्तनीय वरीयता शेयरों ("OCPS") और रिडीमेबल वरीयता शेयरों ("RPS") कीबिक्री को शून्य और निष्प्रभावी घोषित करें, और प्रत्यर्थी संख्या 1 की पुस्तकों में उक्त लेनदेन को वापस लें; यावैकल्पिक रूप से;

b) प्रत्यर्थियों को निर्देश दें कि वे OCPS की बिक्री पर INR 2268.03 करोड़ की हानि के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 कोऔर आनुपातिक रूप से याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करें;

c) प्रत्यर्थियों को निर्देश दें कि वे RPS की बिक्री पर INR 250.42 करोड़ की हानि के संबंध में प्रत्यर्थी संख्या 1 को औरआनुपातिक रूप से याचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करें;

d) प्रत्यर्थियों को निर्देश दें कि वे जिंदल इंडिया थर्मल पावर लिमिटेड ("जिंदल थर्मल" / "प्रत्यर्थी संख्या 15") को ऋणकी अग्रिमता के कारण हुई हानि अर्थात् INR 127.96 करोड़ के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को और आनुपातिक रूप सेयाचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करें;

e) प्रत्यर्थियों को निर्देश दें कि वे जिंदल इंडिया फिल्म्स लिमिटेड (प्रत्यर्थी संख्या 1 की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायककंपनी) द्वारा चंपक निकेतन को जिंदल थर्मल / प्रत्यर्थी संख्या 15 के इक्विटी शेयरों की कम मूल्यांकन पर बिक्री केकारण हुई हानि अर्थात् INR 135.34 करोड़ के लिए प्रत्यर्थी संख्या 1 / जिंदल पॉली को और आनुपातिक रूप सेयाचिकाकर्ताओं को क्षतिपूर्ति प्रदान करें;

f) प्रत्यर्थियों को जिंदल इंडिया पावरटेक लिमिटेड ("जिंदल पावरटेक" / "प्रत्यर्थी संख्या 14") और जिंदल थर्मल / प्रत्यर्थी संख्या 15 के OCPS और RPS या किसी अन्य प्रतिभूतियों के साथ, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, किसी भी रीति से, जिसमें हस्तांतरण, बिक्री, मोचन, किसी भी तरीके से निपटान, या भार का सृजन शामिल है परंतु इन्हीं तक सीमित नहीं है, व्यवहार करने से प्रतिबंधित करें;

g) प्रत्यर्थियों को निर्देश दें कि वे प्रत्यर्थी संख्या 1 कंपनी और याचिकाकर्ताओं को उनकी शेयरधारिता के अनुपात में(जैसा कि पैराग्राफ 8 में उल्लिखित है) उपरोक्त पैरा (b) से (e) में संदर्भित लेनदेन के संबंध में इस माननीयन्यायाधिकरण द्वारा निर्धारित अनुसार, संबंधित हानि की तिथि से 12% प्रति वर्ष चक्रवृद्धि ब्याज सहित क्षतिपूर्ति प्रदानकरें;

h) कंपनी के स्वतंत्र मूल्यांकक के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई का निर्देश दें, क्योंकि उन्होंने कथित रूप से जिंदलपावरटेक / प्रत्यर्थी संख्या 14 और उसके ऋणदाताओं के बीच निष्पादित एक बारगी निपटान पर विचार किए बिनाजिंदल पावरटेक / प्रत्यर्थी संख्या 14 के शेयरों का मूल्यांकन किया और इसलिए प्रत्यर्थी संख्या 1 को गलत या भ्रामकविवरण की सलाह दी;

i) प्रत्यर्थियों को प्रत्यर्थी संख्या 1 और उसके सार्वजनिक शेयरधारकों के मूल्य में कमी के परिणामस्वरूप कोई भी कदमउठाने से प्रतिबंधित करें;

j) इसके अतिरिक्त, याचिकाकर्ता इस माननीय न्यायाधिकरण की अनुमति चाहते हैं कि यदि परिस्थितियाँ इस प्रकार कीअपेक्षा करती हैं, तो बाद के चरण में याचिका में जोड़ने या संशोधन करने की अनुमति दी जाए;

k) अधिनियम की धारा 245 के अंतर्गत उपयुक्त आदेश, अनुतोष, निर्देश पारित करें ताकि उपरोक्त कृत्यों को समाप्तकिया जा सके जो कंपनी और उसके शेयरधारकों के हित के प्रतिकूल हैं और इसके संबंध में आवश्यक आदेश औरअनुतोष के लिए, जिसमें यहां प्रार्थना की गई है; और

l) ऐसे अन्य और/या अतिरिक्त आदेश पारित करें जो माननीय न्यायाधिकरण उचित और समुचित समझे।

इस वर्ग कार्रवाई याचिका के उद्देश्य के लिए वर्ग के सदस्यों का अर्थ JPFL के गैर-प्रमोटर अल्पसंख्यक सार्वजनिकशेयरधारक होंगे, जो इसके 25.46% शेयरधारकों का गठन करते हैं। यदि आप उस वर्ग से संबंधित हैं जिसके संबंध मेंयह आवेदन दायर किया गया है, तो आप इस आवेदन के परिणाम से बाध्य होंगे, जब तक कि आप न्यायाधिकरण कीअनुमति के अधीन, सुनवाई की अगली तिथि तक प्रासंगिक प्रपत्र, प्रपत्र NCLT-1, उपरोक्त नियमों के परिशिष्ट-B मेंउल्लिखित ऐसे दस्तावेजों के साथ निम्नलिखित पते पर प्रस्तुत करके कार्यवाही से बाहर निकलने का निर्णय नहीं लेते: ब्लॉक संख्या 3, भूतल, 6वीं, 7वीं मंजिल एवं 8वीं मंजिल, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली - 110 003।

दिनांक: 06.02.2026
स्थान: नई दिल्ली
हस्ता०/-
हस्ताक्षर: (रजिस्ट्रार, राष्ट्रीय कंपनी विधि न्यायाधिकरण, प्रधान पीठ)

TRUE COPY

CCI NG 3.17 Product: ETDelhiBS PubDate: 09-02-2026 Zone: Lucknow Edition: 1 Page: ETLPAGE9 User: samar.jha@timesofindia.com Time: 02-08-2026 22:03 Color:

ET Q&A

PIYUSH GOYAL
COMMERCE AND INDUSTRY MINISTER

When I talk to America and say our intention is to import at least $500 b, I think we can even do more than that. It's for the importers in India and exporters in America to get a good deal and strike bargains

US-India Pact a Growth Engine for Jobs, Tech & Trade

India's intent to buy critical goods worth $500 billion, including energy, from the US will help diversify sources for these products, commerce and industry minister Piyush Goyal told **Kirtika Suneja**, **Deepshikha Sikarwar** and **Vinay Pandey** in an interview. These will be drivers for India's growth story as it becomes a $30 trillion economy by 2047. Edited excerpts:

The opposition is criticising the agreement, particularly on agriculture…
The agreement is very fair and balanced. It actually leaves no scope for criticism. It protects all of India's sensitive interests and provides huge opportunities for our labour-intensive sectors. It opens the floodgates to technology, which India needs to become a superpower, to become a global economy and investments for that. It will provide a great impetus for exports, both of goods and services.

The narrative in some quarters is that India is giving much more than it is getting. How do you respond to this?
I monitored social media in the last week very extensively and I can correct your perception with data to show you the overwhelming support for this first tranche of the BTA (bilateral trade agreement). There is a small Congress-related ecosystem, many of them possibly from outside India, and it is their job to oppose… (they) have not yet raised any substantive issue. As regards giving away more and receiving less, all trade agreements are very equitable and have to be a win-win for both parties. In our case, we are very conscious of national interests and public interest. We've done a very calibrated opening of the Indian market, focused on job creation in India and areas of our interest, and protected sensitivities. I, with full responsibility, say there is no scope to find fault in this agreement.

What would you tell India's farmers at this stage?
Well, I'll tell India's farmers that all the sensitive items in agriculture have been fully protected with a very carefully crafted exclusion list, where we have given no concessions whatsoever. Broad categories, among others, include dairy and all GM foods, where there is no opening. No concessions on soy meal, corn, cereals like rice and wheat, sugar, meat and poultry, millets, fruits like banana, strawberries, cherries, citrus fruits, pulses like green pea, Kabuli chana, moong, oil seeds, certain animal feed, non-alcoholic beverages, flour, starch, essential oils, ethanol for fuel, tobacco. All these are excluded from any concessions. Frankly, after this, there is no cause left for any farmer to complain. There are certainly certain products we have been importing for many years, from the time Congress was in government. That time also you had soybean oil and tree nut imports. So, there are certain items where India does not have enough production, which we continue to import. There is an opening.

EU FTA AND CHINA+1

We wish to see India as a part of resilient supply chains, but on our own strength, our capabilities, and not because it's a compulsion of another country

Did the successful clinching of the EU deal create an environment for the US to move ahead quickly?
Every trade deal stands on its own feet and on its own strengths. It's a matter of coincidence. Both deals have been under negotiation for a long time. EU (took) much longer; it started in 2006. It's very sad that the Congress and its partners could not close that deal despite intense negotiations. The Europeans were so frustrated that they gave up on India…We had elections in mid of 2024 and the EU in the third quarter of 2024. They appointed a new trade commissioner (Maroš Šefovi) on December 1, 2024, who is one of their most seasoned commissioners. Their intention was that they wanted to have a robust agreement with India. So clearly, from around January last year, negotiations intensified. So, both these trade agreements were concluded almost simultaneously. The EU between January 2025 and January 2026, and the US, between March 2025 and almost January 2026.

How will this $500 billion purchase intent that's part of the deal work, and does it take away from any of our other trade partners?
India, even today, imports about $45-50 billion worth of goods from the US. These are goods which we need in India to power and grow our economy. We import aeroplanes, engines, and their spare parts. We already have orders worth $50 billion for aeroplanes, plus orders for engines and spare parts, probably $88 billion or so. I'm told by our airline operators that they want to further increase orders. They need more planes; India's demand is growing so rapidly for air travel. So we need at least $100 billion of aviation-related equipment in the next five years.

Our steel production, at 140 mt, is slated to grow to 300 mt. Today, we are importing coking coal of 15-17 million (tonnes) a year, and it can easily become 30 million (tonnes) a year… 150 million (tons) of coking coal is required in five years or a little less. We need sources for our energy requirements. Today, the imports of data centres, AI machinery, quantum computing equipment, and ICT (information and communications technology) products are growing at almost double-digit plus… 15-20%. When you look at the context of all of these imports, where we have no choice but to import… precious metals, we continue to import, and it's not from today, all of these have been imported for decades. We estimated that even today, about $300 billion of our imports are only in these limited products I mentioned, which will be required in large quantities. In the next five years our estimate with the growth that we are demonstrating is that just these products, we need $2 trillion in the next five years. So when I talk to America and say our intention is that we should import at least $500 billion, I think we can even do more than that. It's for the importers in India and exporters in America to get a good deal and strike bargains.

Why should we have only two countries from which we get coking coal? The more the merrier–we get better prices, better deliveries. On ICT products, is there any other country that can be a trusted partner of India to provide us with chips like Nvidia chips or provide us with AI equipment? They are the only country that has all of this equipment. And look at the budget announcements. We will need all of these for our AI mission, permanent magnet mission, and for our data centre mission. We will need all of this. Our energy needs are growing 5-8%. In all of these products, competition only makes Indian purchasing more efficient for better for our consumers. If India has to become a $30 trillion economy by 2047, these will be the drivers of that growth story.

TRADE & TIES WITH US

The US-India relationship is in perpetuity. Our partnership and strategic cooperation is in perpetuity and, therefore, trade will be in perpetuity

The framework talks about coordination on non-market policies of third parties. What is it alluding to, and how will this play out specifically in the backdrop of India's relationship with China?
I think you are assuming something here. India and the US are two of the world's largest democracies. We have fair play and open market policies. We don't create unfair trade barriers. Both countries are known to have very good quality standards and focus on fair pricing and fair play. And, therefore, we believe we should encourage greater trade among like-minded countries, which is the intention of that paragraph.

India, for some time, has been aspiring to emerge as an alternative place of manufacturing—the China+1 strategy. With this development and FTA with the EU, how do you see it being reinforced?
I have very often said India does not depend on anybody else's focus to diversify from any particular geography. We understand that all companies would like to have diversified and more resilient supply chains. We wish to see India as a part of those resilient supply chains, but on our own strength, our capabilities, and not because it's a compulsion of another country.

Typically, India's conventional trade agreements are in perpetuity. But this is not a conventional trade pact. Is this also in perpetuity?
The US-India relationship is in perpetuity. Our partnership and strategic cooperation is in perpetuity and, therefore, trade will be in perpetuity. Robust, fair trade is what we would like to encourage.

The framework talks about addressing "discriminatory and burdensome" practices in digital trade. What is it alluding to?
India is one of the most important providers of digital services to almost the entire world today. Our IT and digital services sectors have grown rapidly. The US is a very important market. Likewise, the US has huge capabilities on technology related services. We would like both countries to work in a spirit of cooperation and engage with each other with more opportunities for our businesses. To ensure that on both sides there's free flow, easier working conditions and ensure that at any point of time, we continue to give the most preferred status to each other and remove any roadblocks or impediments to greater digital trade between the two countries. Which is why you would also observe in the same agreement that we have talked of ICT products–where we need equipment from the US and we need their continued support to ensure that the trade in technology products, including GPUs and other goods use in data centres. (This) will be a part of our joint technology corporation.

Data protection has been a matter of contention between the two countries. Will these concerns be addressed?
Every country in the world looks after its people's data. But at the same time, in an interconnected world, it is important to also have the ability to move data faster and ensure that data becomes a driver of the growth engine of your economy. So, our effort will be to leverage the huge amounts of data that we have, not bring impediments on its utilisation or conversion into economic activity, at the same time, ensuring the protection of data and the privacy laws being respected.

DATA & PROTECTION

Our effort will be to leverage huge amounts of data we have, not bring impediments on its utilisation... while ensuring the protection of data

Will the ICT import licensing arrangement be on a case-by-case basis or a mutual recognition regime?
On ICT products, we want our requirements to be met by trusted partners. And, therefore, we should look at expanding relations and expanding trade between countries who believe in fair play and equal opportunity to trade inter se. Therefore, we are very keen to expand our technology collaborations. This is a broad framework; details will be worked out soon.

Would we be able to impose digital taxes, if required?
We are already at the WTO working on ecommerce moratorium, which is a part of our global agenda. One must not forget that today, with India's large amount of digital services, we have to tread with caution on this subject. It is a sword that cuts both ways.

India now has trade deals with developed nations. In the past, Indian industry has been found wanting in taking advantage of these pacts. How are you gearing up the industry in view of these new trade deals?
I am intensely engaged with the industry. I am working with them to help them grow, expand their scale of operations, think outwardly, focus on quality, think big and get out of the cosy comfort of the large Indian market. I have been receiving very good feedback. There is a sense of enthusiasm and excitement about the new opportunities. Earlier, we did not have free trade deals with developed countries. There was always a sense of fear that they would not be able to compete with other countries and export to those geographies at lower duties. Now we have the lowest duty. For example, in the EU, all textiles are at zero duty, and in the US, we have the lowest duty on textiles. Our textiles sector is raring to go.

FOR FULL INTERVIEW, GO TO
www.economictimes.com